Influx of refugees from Bangladesh

*57. SHRI KAILASH PATI MISHRA:

SHRI ASHWANI KUMAR:

Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether there has been a fresh and heavy influx of refugees from Bangladesh due to increasing religious intolerance there; if so, since when and how many persons have arrived as yet;

(b) what is the estimated number of refugees who have arrived in India since the creation of Bangladesh; and

(c) whether these refugees having been driven out from their homes and lands, are now demanding for themselves a 'Homeland'; if so, what is Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI P. V. NARASIMHA RAO): (a) and (b) The problem of illegal immigration from Bangladesh into India has been growing. Recent trend in the number of members of Bangladesh's minority communities entering India illegally has been one of expansion. Persons who enter the country illegally do not register themselves and, therefore, no accurate figures of illegal immigrants are available.

(c) Some reports to this effect have been seen. Government disapprove of any such activity on Indian soil.

एशियाई विकास बैंक की मदद से सड़कों का विकास

*58. श्री **सन्तोष बागडोदिया**: क्या **जल भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक भारतीय सड़कों के विकास के लिए सहायता प्रदान करने के लिए सहमत हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर "हां" हो, तो इस प्रयोजन के लिए राजस्थान राज्य की किन-किन परियोजनाओं को अंतिम रूप दे दिया गया है और प्रत्येक परियोजना की अनुमानित लागत कितनी-कितनी है?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट): (क) जी हां।

(ख) गुजरात, हरियाणा, पंजाब तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए विश्व बैंक 200 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण सहायता देने पर सहमत हो गया है।

राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार राज्यों में राज्य क्षेत्रीय परियोजनाओं के लिएविश्व बैंक आई० डी० ए० ऋण सहित 250 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण सहायता देने पर सहमत हो गया है।

एशियाई विकास बैंक—आंध्र प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यों तथा आंध्र प्रदेश कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों में राज्य की क्षेत्रीय सड़क परियोजनाओं के लिए 198 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण सहायता देने पर सहमत हो गया है।

(ग) राजस्थान में राज्य की जो सड़क परियोजनाएं विश्व बैंक ऋण में सम्मिलित हैं उनका ब्यौरा इस प्रकार है

	लम्बाई	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत (मिलियन रुपए
अलवर-भिवाड़ी	90.0 कि. मी.	सुदृढ़ करना और दोहरी लेन में चौड़ा करना	119.50
अलवर-करौली	143.0 कि. मी०	सुदृढ़ करना और दोहरी लेन में चौड़ा करना	153.70

	लम्बाई	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत (मिलियन रुपए)
उदयपुर-देवोक	16.0 कि० मी०	सुदृढ़ करना और इहरी लेन में चौड़ा करना	70.80
देवोक-चित्तौड़गढ़	97.0 कि० मी०	सुदृढ़ करना और दोहरी लेन में चौड़ा करना	106.00
अजमेर-चित्तौड़गढ़	186.0 कि० मी०	सुदृढ़ करना और दोहरी लेन में चौड़ा करना	221.90
सिरोही-आबू रोड	63.0 कि० मी०	सुदृढ़ करना और दोहरी लेन में चौड़ा करना	57.00
आबू रोड-माउंट आबू	23.0 कि० मी०	सुदृढ़ करना और दोहरी लेन में चौड़ा करना	24.30
फतेहपुर-चुरू	36.0 कि० मी०	सुदृढ़ करना और दोहरी लेन में चौड़ा करना	27.20
चुरू-हरियाणा सीमा	79.0 कि० मी०	सुदृढ़ करना और दोहरी लेन में चौड़ा करना	56.80
सीकर-हरियाणा सीमा	133.0 कि० मी०	सुदृढ़ करना और दोहरी लेन में चौड़ा करना	113.10

Transfer of the management of Hotel Corporation of India to ITDC

*59. SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: Will the Minister of CIVIL AVIATION AND TOURISM be pleased to state:

(a) whether there is any proposal under Government's consideration to transfer the management of Hotel Corporation of India to ITDC; and

(b) if so, what are the reasons therefor and the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISRY OF CIVIL AVIATION AND TOURISM (SHRI SHIVRAJ PATIL): (a) and (b) The National Committee on Tourism has recommended the merger of the Hotel Corporation of India with the India Tourism Development Corporation. Modalities are being examined by the Government.

Compensation to the victims of air crashes

*60 SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: Will the Minister of CIVIL AVIATION AND TOURISM be pleased to state:

(a) what is the position of the amount of compensation to be paid to the families of air-crash victims according to the International Notification under the (i) Warsaw Convention; (ii) Hague Protocol; (iii) Guatemala Convention and (iv) Government of India Notifications of 1973 and 1980; and

(b) whether Government have received requests to revise the amounts; if so, what are the details thereof and what is Government's response thereto?